



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032025-262117
CG-DL-E-29032025-262117

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1489]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947

No. 1489]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2025

का.आ. 1507(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शूलपानेश्वर वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात के आसपास पारिस्थितिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1653(अ), तारीख 5 मई, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1653(अ), तारीख 5 मई, 2016 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन

मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1653(अ), तारीख 5 मई, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-

“5. निगरानी समिति. – (1) केंद्रीय सरकार एक निगरानी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

- | | | |
|--------|---|-------------------|
| (i) | क्लेक्टर, जिला नर्मदा | अध्यक्ष, पदेन; |
| (ii) | क्षेत्र के संसद सदस्य* | सदस्य, पदेन; |
| (iii) | संबंधित जिला पंचायत के अध्यक्ष | सदस्य, पदेन; |
| (iv) | गुजरात सरकार के आदिवासी विकास विभाग के प्रतिनिधि | सदस्य, पदेन; |
| (v) | क्षेत्र के वरिष्ठ नगर नियोजक | सदस्य, पदेन; |
| (vi) | पर्यावरण या वन्य जीव (विरासत संरक्षण सहित) के क्षेत्र में काम करने वाले एक गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे प्रत्येक तीन वर्ष के लिए गुजरात सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। | सदस्य; |
| (vii) | प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे प्रत्येक तीन वर्ष के लिए गुजरात सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। | सदस्य; |
| (viii) | गुजरात सरकार के वन एवं पर्यावरण विभाग का एक प्रतिनिधि | सदस्य, पदेन; |
| (ix) | क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला नर्मदा | सदस्य, पदेन; |
| (x) | उप वन संरक्षक, (शूलपनेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के प्रभारी), नर्मदा जिला | सदस्य सचिव, पदेन। |

*गुजरात राज्य सरकार द्वारा अन्य तथ्यों के साथ-साथ लोक सभा अध्यक्ष की अनुमति सहित प्रासंगिक अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन

- (2) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जब कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अधीन आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन दी गयी सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राजकीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गये हैं।
- (3) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों के पास भेजा जाएगा।
- (4) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या संबंधित क्लेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करने के लिए सक्षम होंगे।

- (5) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।
- (6) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव बोर्ड को उपाबंध-III में निर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।
- (7) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।

[फा.सं. 25/121/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक "जी"

टिप्पण.-- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 5 मई, 2016 की विस्तृत का.आ. 1653(अ), द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2025

S.O. 1507(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary, Gujarat in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1653(E), dated the 5th May, 2016;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1653(E), dated the 5th May, 2016;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1653(E), dated the 5th May, 2016, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

“5. **Monitoring Committee-** The Central Government hereby constitute a monitoring Committee consisting of the following persons, namely: —

- | | | |
|-------|---|-------------------------------|
| (i) | Collector, Narmada District | Chairman, <i>ex-officio</i> ; |
| (ii) | Member of Parliament of the area* | Member, <i>ex-officio</i> ; |
| (iii) | President of Concerned Zila Panchayat | Member, <i>ex-officio</i> ; |
| (iv) | Representative of Tribal Development Department, Government of Gujarat | Member, <i>ex-officio</i> ; |
| (v) | Senior Town Planner of the area | Member, <i>ex-officio</i> ; |
| (vi) | One representative of a Non-Governmental Organisation working in the field of Environment or Wildlife (including heritage conservation) to be | Member; |

nominated by the Government of Gujarat from time to time every three years

- | | | |
|--------|---|--|
| (vii) | An expert in the area of ecology and environment from reputed institution or University to be nominated by the Government of Gujarat from time to time every three years. | Member; |
| (viii) | A representative of the Department of Forest and Environment, Government of Gujarat | Member, <i>ex-officio</i> ; |
| (ix) | Regional Officer, State Pollution Control Board, Narmada District | Member, <i>ex-officio</i> ; |
| (x) | Deputy Conservator of Forests, (incharge of Shoolpaneshwar Wildlife Sanctuary), Narmada District | Member Secretary,
<i>ex-officio</i> . |

*Subject to the State Government of Gujarat obtaining relevant approvals inter alia including permission from the Speaker of Lok Sabha

- (2) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (2) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representative or expert from the Department concerned, representative from industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in proforma specified in Annexure-III.
- (7) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.”.

[F. No. 25/121/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note. —The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O. 1653(E), dated the 5th May, 2016.